रामफल बनाम माया देवी और अन्य

(न्यायमूर्ति राजबीर सेहरावत)

न्यायमूर्ति राजबीर सेहरावत के समक्ष

रामफल---------- अपीलकर्ता

बनाम

माया देवी और अन्य------ प्रतिवादीगण

सीआर No.3077/2015

20 जनवरी, 2020

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 227- पुनर्निरीक्षण याचिका-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-ओ. 7 आर. 11 और एस. 9 द्वारा -दावा भूमि के स्वामित्व और कब्जे का दावा करने वाले प्रतिवादी/वादी द्वारा दावे की घोषणा का मुक़दम्मा, जो याचिकाकर्ता/प्रतिवादी, जो वादी का बेटा है, द्वारा पूर्व अनुमति से खेती की जा रही थी-सह-वादी नंबर 2 मुकदमे की जमीन में आधे हिस्से का मालिक था- यह घोषणा भी मांगी गई थी कि लोक अदालत अवार्ड दिनांक 06.03.2006 वादी पर बाध्यकारी नहीं था क्योंकि उसे कभी भी ऐसा नुकसान नहीं उठाना पड़ा-यह अवार्ड प्रतिवादी द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे का परिणाम था जिसे लोक अदालत के समक्ष रखा गया था-वादी कभी भी लोक अदालत के लिए उपस्थित नहीं हुई या किसी वकील को नियुक्त नहीं किया, उसे कभी भी कोई समन नहीं भेजा गया था - यह अवार्ड गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया था और यह वादी के साथ-साथ लोक अदालत पर भी धोखाधड़ी था - धोखाधड़ी का पता चलने पर, वादी ने पहले

अवार्ड को चुनौती देने के लिए एक और मुकदमा दायर किया था, हालांकि, उसके बेटे ने प्रतिवादी के आश्वासन पर कि वह इससे किसी भी लाभ का दावा नहीं करेगा। न ही मुकदमे की जमीन बेचेगा, इसे वापस ले लिया था - अब प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर रहा था - इसलिए, तत्काल मुकदमा दायर किया गया - याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने दलील दी क्योंकि लोक अदालत द्वारा पक्षों के बीच समझौते के आधार पर एक फैसला सुनाया गया था , इसे चुनौती देने वाला मुकदमा चलाने योग्य नहीं था - भार्गवी कंस्ट्रक्शन केस 2017

(4) आरसीआर (सिविल) 359 के अनुसार वादी के पास अवार्ड के खिलाफ एक रिट याचिका दायर करने का उपाय उपलब्ध था इसके अलावा, पहला मुकदमा एक नया मामला दायर करने की अनुमति के बिना वापस ले लिया गया था, और इसलिए पुनर्न्याय के सिद्धांत पर भी रोक लगा दी गई थी – ओ.7 आर.11 सीपीसी के खंड (डी) के प्रावधानों के तहत, ट्रायल कोर्ट को केवल दावे में वादी के दिए गए कथनों पर गौर करना होगा - ओ.7 आर.11 सीपीसी के तहत दावे को खारिज करते समय कोई विवादित तथ्य ट्रायल कोर्ट द्वारा तर्क या उस पर विचार नहीं किया जा सकता है - फिर भी, एस.9 सीपीसी निर्धारित करता है कि नागरिक अधिकारों से जुड़े हर मुकदमे को सिविल कोर्ट के समक्ष दायर किया जा सकता है जब तक कि स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित न हो –रखरखाव के दीवानी मुकदमे को छोड़ कर -- जो केवल एक अपवाद है, जिसकी कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए| तथ्यों पर, तत्काल दीवानी मुकदमे को रोकने का कोई प्रावधान अदालत को नहीं दिखाया गया था - भार्गवी निर्माण मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अलग था, क्योंकि उस मामले में लोक अदालत के समक्ष वादी की उपस्थिति कभी

विवादित नहीं थी - जबकि, तत्काल मामले में, वादी का दावा है कि अवार्ड लोक अदालत द्वारा उसकी उपस्थिति या नोटिस के बिना पारित किया गया था, और प्रतिरूपण के माध्यम से धोखाधड़ी थी-इसलिए, वादी को उन कार्यवाहियों का हिस्सा नहीं माना जा सकता है-आगे कहा गया, यह अच्छी तरह से तय किया गया था कि धोखाधड़ी पर आधारित किसी भी आदेश को, भले ही सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त किया गया हो, दीवानी अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सकती है-तत्काल मुकदमे में भी धोखाधड़ी को चुनौती दी गयी है अदालत को नहीं, इसलिए यह चलाया जा सकता है - इसके अलावा, पुनर्न्याय का सिद्धांत कानून और तथ्यों के एक मिश्रित प्रश्न को ओ.7 आर.11 सीपीसी के तहत एक आवेदन को बनाए रखने के लिए आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है, ऐसे आवेदन के लिए दलीलों को सही माना जाना चाहिए, केवल तभी न्यायालय को यह आकलन करना होगा कि ओ.7 आर.11 सीपीसी के तहत आधार मौजूद हैं या नहीं -फिर भी, चूंकि सह-वादी न तो पहले के मुकदमे में या लोक अदालत से पहले की कार्यवाही में एक पक्ष नहीं था, इसलिए मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता था-याचिका खारिज कर दी गई।

यह माना गया कि आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के खंड (डी) का केवल अवलोकन, जिस पर याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा एकमात्र निर्भरता रखी गई थी, यह दर्शाता है कि दावे को निचली अदालत द्वारा केवल तभी खारिज किया जा सकता है जब यह प्रतीत होता है कि दावे में किए गए अभिकथनों को किसी भी कानून द्वारा वर्जित किया गया है। इसलिए, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, निचली अदालत को केवल दावे में किए गए कथनों पर

गौर करना होगा। शिकायत में किए गए कथनों को फिलहाल के लिए और आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के उद्देश्य के लिए सही माना जाना चाहिए। आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत दावे को खारिज करने के लिए निचली अदालत द्वारा तथ्य के किसी भी विवादित प्रश्न पर तर्क नहीं दिया जा सकता है या उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 7)

आगे कहा कि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सी. पी. सी. की धारा 9 की उपरोक्त भाषा यह स्पष्ट करती है कि किसी भी नागरिक अधिकार के उल्लंघन का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया कोई भी मुकदमा, किसी भी संपत्ति के अधिकार से बहुत कम, अनिवार्य रूप से बनाए रखने योग्य है।दीवानी मुकदमे की रखरखाव क्षमता का बहिष्करण केवल एक अपवाद है।उस अपवाद की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए, अन्यथा, किसी भी उदार व्याख्या से पीड़ित व्यक्ति को सुनने के अवसर से वंचित किया जा सकता है, जो की स्वयं में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए बाध्य है।

(पैरा 9)

आगे कहा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील इस न्यायालय का ध्यान किसी भी वैधानिक प्रावधान की ओर आकर्षित करने में सक्षम है, जो वर्तमान दावे को प्रतिबंधित करता है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भार्गवी कंस्ट्रक्शंस (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर

भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक फैसले के माध्यम से निर्धारित कानून भी एक कानून है, जिसका प्रभाव वर्तमान मामले में दीवानी मुकदमे पर रोक लगाने का होगा। हालाँकि, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलों से सहमत होने में असमर्थ है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भार्गवी कंस्ट्रक्शंस (ऊपर) में दिए गए निर्णय पर निर्धारित कानून की पूर्व स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है, जो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया जा रहा है, हालांकि, इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामला उस मामले में शामिल तथ्यों पर पूरी तरह से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि उस मामले में वादी ने कभी भी लोक अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया था।उनका एकमात्र दावा सबसे अच्छा था यह था कि उन्होंने मुकदमे के दायरे को नहीं समझा था या उन्हें किसी गलत बयानी से गुमराह किया गया था।उस मामले में लोक अदालत के समक्ष पूर्ण अनुपस्थिति का अनुरोध भी नहीं किया गया था।इसलिए, उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति, जो निर्विवाद रूप से लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार था, को लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कोई शिकायत थी, तो वह उक्त निर्णय को चुनौती देने के लिए रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।उस मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित पक्ष को उपचार के बिना नहीं छोड़ा था, लेकिन चूंकि

लोक अदालत का निर्णय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत अपील योग्य नहीं था, इसलिए पीड़ित व्यक्ति को रिट याचिका के उपचार का हकदार ठहराया गया था।हालाँकि, वर्तमान मामले में, दावे में वादी का सकारात्मक दावा और कथन यह है कि उन्हें कभी भी उन कार्यवाही में अदालत से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था जहां लोक अदालत ने उक्त पुरस्कार पारित किया था।उक्त अवार्ड वादी के प्रतिरूपण के माध्यम से की गई धोखाधड़ी पर आधारित था।उस स्थिति में, वादी को उक्त कार्यवाही में पक्षकार के रूप में भी नहीं लिया जा सकता है।अतः, वादी द्वारा दायर मुकदमे में कोई दोष नहीं पाया जा सका।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि धोखाधड़ी पर आधारित कोई भी आदेश, भले ही वह सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश हो; लेकिन धोखाधड़ी के माध्यम से, दीवानी न्यायालय के समक्ष बहुत अच्छी तरह से चुनौती दी जा सकती है।इस तरह के मुकदमे को बनाए रखने योग्य बनाने का कानूनी सिद्धांत यह है कि ऐसे मुकदमे में चुनौती धोखाधड़ी को दी जाती है, न कि अदालत के आदेश को। कानून को धोखेबाज के पक्ष में खड़े होते हुए भी नहीं देखा जा सकता, उसकी रक्षा करना तो दूर की बात है। वर्तमान मामले में, जहां तक कथनों का संबंध है, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन के उद्देश्य के लिए, यह विवादित नहीं है कि वादी ने विशेष रूप से दावा किया है कि उसका प्रतिरूपण किया गया था। इसलिए, केवल इसी कारण से; उसका सूट पूरी तरह से

रखरखाव योग्य है। इस संबंध में निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में कोई गलती नहीं पाई जा सकी।

(पैरा 10)

आगे कहा कि जहां तक याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए दूसरे बिंदु का संबंध है, इस न्यायालय को निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।यह भी एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि न्यायपालिका कानून और तथ्यों का एक मिश्रित सवाल है।किसी भी पहलू, जो कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है, को आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को बनाए रखने के लिए एक आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के उद्देश्य के लिए, दलीलों को सही माना जाना चाहिए और उसके बाद ही न्यायालय को यह आकलन करना होगा कि आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. में उल्लिखित आधारों में से कोई भी मौजूद है या नहीं।इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के इस तर्क को भी केवल अस्वीकार करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(पैरा 11)

आगे कहा कि इस न्यायालय ने प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में भी दम पाया कि, कम से कम, वादी संख्या 2 लोक अदालत के समक्ष या पहले के मुकदमे में कार्यवाही का पक्षकार नहीं था,

जिसे केवल वादी संख्या 1 द्वारा दायर और वापस लिया गया था।चूँकि वादी सं. 2 भी वर्तमान मुकदमे में एक सह-वादी है, इसलिए वर्तमान दावा को आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था कि मुकदमा पुनर्निरीक्षण के कारण बनाए रखने योग्य नहीं था या वादी सं. 1 द्वारा पहले के मुकदमे को वापस लेने के कारण या रोक दिया गया था। दावे में किए गए अभिकथनों के अनुसार, पहले के मुकदमे को वापस लेने का कारण यह था कि प्रतिवादी द्वारा किए गए वादे के कारण कार्रवाई का कारण अस्तित्व में नहीं था, जो केवल वादी संख्या 1 का बेटा है। वर्तमान मुकदमा कार्रवाई के नए कारण पर दायर किया गया है।

(पैरा 12)

अजय जैन, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए

एस. एल. बरवाला, अधिवक्ता प्रतिवादीगण के लिए

राजबीर सहरावत, जे. ओरल

(1) यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन), हिसार द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.3.2015 को चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत

दायर आवेदन निचली अदालत ने खारिज कर दिया है।

(2) वर्तमान याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादियों/वादियों द्वारा यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था कि वादी नंबर1, भूमि मुकदमा 87 कनाल 2 मरला का मालिक है, जिसमें खेवट संख्या 341, खटोनी संख्या 514 शामिल है, जो जमाबंदी वर्ष 2000-01 के अनुसार, गाँव बढावर, तहसील बरवाला, जिला हिसार में स्थित है और प्रतिवादी, जो वादी संख्या 1 का बेटा है, वादी संख्या 1 की पूर्व अनुमति से उपरोक्त भूमि पर खेती कर रहा है, वादी संख्या 2 मौखिक पारिवारिक समझौते के अनुसार उपरोक्त भूमि के 1⁄2 हिस्से का मालिक है, और आगे यह कि लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 6.3.2006 का निर्णय, उसके लिए बाध्यकारी नहीं था। क्योंकि उन्हें कभी ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिला था. दरअसल, वर्ष 2000-01 की जमाबंदी के अनुसार वादी संख्या 1 स्वयं भूमि दावा की मालिक है। प्रतिवादी, जो उसका बेटा है, ने उसकी अनुमति से भूमि पर खेती शुरू कर दी। हालाँकि, द्वारा पारित किया गया है।वास्तव में, वादी संख्या 1 स्वयं वर्ष 2000-01 के लिए जामबंदी के अनुसार मुक़दमे की भूमि का मालिक है।प्रतिवादी, जो उसका बेटा है, ने उसकी अनुमति से भूमि पर खेती करना शुरू कर दिया।हालाँकि, बाद में उन्हें पता चला कि याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था।अंततः उस मुकदमे को लोक अदालत के समक्ष रखा गया।वादी कभी भी लोक अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ, कभी किसी वकील को नियुक्त नहीं किया और उस मुकदमे में कभी कोई लिखित बयान दायर नहीं किया।वास्तव में, वादी को उस

मुकदमे में कभी भी अदालत से कोई समन नहीं दिया गया था।अतः, उस दावे में अवार्ड वादी के प्रतिरूपण के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जिससे वादी के साथ-साथ लोक अदालत के साथ धोखाधड़ी की गई।जब वादी को इस तथ्य के बारे में पता चला, तो उसने एक और दीवानी मुकदमा संख्या 932/सी/2012 दायर किया था।हालाँकि, इसके बाद प्रतिवादी, जो वादी का बेटा है, ने आश्वासन दिया कि वह उक्त संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचेगा और लोक अदालत के फैसले से किसी भी लाभ का दावा किए बिना, उसे वादी संख्या 1 के नाम पर स्थानांतरित कर देगा।इसलिए, प्रतिवादी/याचिकाकर्ता के इस आश्वासन पर कार्रवाई करते हुए, वादी संख्या 1 द्वारा उक्त मुकदमा वापस ले लिया गया था।इसके बाद वादी ने प्रतिवादी से उपरोक्त भूमि को उसके नाम पर हस्तांतरित करने के लिए कहा।हालाँकि, प्रतिवादी ने वादी के नाम पर उक्त भूमि को हस्तांतरित करने के बजाय वादी संख्या 1 को घर से बाहर कर दिया था।इतना ही नहीं, वादी को पता चला कि प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित कर रहा था।इसलिए, वर्तमान मुकदमा दायर किया गया था।

(3) अपने मामले में तर्क देते हुए, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि लोक अदालत द्वारा पारित एक अवार्ड मौजूद है, जो पक्षों के बीच समझौते पर आधारित है, इसलिए, अवार्ड को चुनौती देने वाला मुकदमा सिविल कोर्ट के समक्ष दायर नहीं किया जा सकता था।यदि बिल्कुल भी हो कि वादी लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय से व्यथित था,

तब वादी के लिए उपलब्ध उपाय दीवानी मुकदमा दायर करना नहीं था, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भार्गवी निर्माण और अन्य बनाम कोठाकापु मुथियम रेड्डी और अन्य में दिए गए फैसले के अनुसार, लोक अदालत द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करना था। चूंकि इस विधि बिंदु का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के द्वारा किया गया है, इसलिए, वादी द्वारा दीवानी न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमे को कानून द्वारा रोक लगा दी गई थी।इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन को निचली अदालत द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए थी।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे पहले भी वादी संख्या 1 ने लोक अदालत के उसी फैसले के खिलाफ एक और मुकदमा दायर किया था, हालांकि, वादी संख्या 1 द्वारा नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के बिना इसे वापस ले लिया गया था, इसलिए, वर्तमान में पुनर्निर्णय द्वारा भी मुकदमे पर रोक लगा दी जाएगी।

(4) दूसरी ओर, प्रतिवादीगण/वादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा मुकदमा सही ढंग से दायर किया गया था। प्रतिवादी /वादी संख्या 1 कभी भी किसी भी अदालत या लोक अदालत के समक्ष उन कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं हुआ जिनमें अवार्ड उत्पन्न हुआ है।जहाँ तक वादी संख्या 1 द्वारा दायर दूसरे मुकदमे का संबंध है, वह मुकदमा केवल तभी वापस लिया गया था जब प्रतिवादी अवार्ड के आधार पर कुछ भी दावा नहीं करने के लिए सहमत हुआ था।वादी संख्या 1, प्रतिवादी की माँ

होने के नाते प्रतिवादी के शब्दों पर विश्वास करती थी और कार्रवाई का कारण अस्तित्व में नहीं था।हालाँकि, प्रतिवादी ने अवार्ड के आधार पर संपत्ति पर फिर से दावा करना शुरू कर दिया था, जिससे कार्रवाई का नया कारण सामने आया।किसी भी मामले में, केवल वादी में से किसी एक वादी द्वारा मुकदमा दायर किया गया था और वादी संख्या 2 या तो वादी संख्या 1 द्वारा दायर किए गए दूसरे मुकदमे में या उस मुकदमे में भी एक पक्ष नहीं था जिसमें लोक अदालत द्वारा अवार्ड पारित किया गया था। इसलिए, किसी भी तरह से, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन को निचली अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता था।इसलिए, निचली अदालत ने इसे सही ही खारिज कर दिया है। निचली अदालत द्वारा पारित वैध और सुविचारित आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सका।

(5) निचली अदालत द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने के लिए विशिष्ट कारण दिए हैं।निचली अदालत ने लिखा है कि यह प्रतिरूपण और परिणामी धोखाधड़ी का मामला है, न कि केवल लोक अदालत से अवार्ड प्राप्त करने में गलत प्रतिनिधित्व का। इसलिए, वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा कायम रखने योग्य है।दूसरा दिए गए दावे में, जिसे वादी संख्या 1 द्वारा वापस ले लिया गया था, न्यायालय ने नीचे लिखा है कि प्रतिवादी की याचिका मामले को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लेने के लिए है। हालाँकि, न्यायनिर्णयन का प्रश्न कानून और

तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है, जिसका निर्णय पक्षकारों द्वारा साक्ष्य के नेतृत्व के बाद ही किया जा सकता है, न कि आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन के निर्णय के स्तर पर। तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिया गया।

(6) संबंधित पक्षों की ओर से वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता/प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलों में कोई दम नहीं है।वर्तमान मामले के उचित निर्णय के उद्देश्य से, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. में निहित प्रावधानों के संदर्भ के लिए आवश्यक है, जिसे यहां निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

आदेश VII नियम 11-दावे की अस्वीकृति-दावा निम्नलिखित मामलों में अस्वीकृत किया जाए -

(क) जहाँ यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है;

(ख) जहां दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया गया है, और वादी, अदालत द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए अदालत द्वारा आवश्यक होने पर, ऐसा करने में विफल रहता है;

(ग) जहाँ दावा की गई राहत का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन वाद अपर्याप्त स्टांप कागज पर लिख जाता है, और वादी, अदालत द्वारा आवश्यक होने पर, अदालत द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर आवश्यक स्टांप पेपर की आपूर्ति करने में विफल रहता है;

(घ) जहाँ दावा, दावे में दिए गए कथन से किसी भी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है;

(ई) जहां यह डुप्लिकेट में दाखिल नहीं किया गया है;

(च) जहाँ वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता हैः

बशर्ते कि मूल्यांकन में सुधार या अपेक्षित स्टाम्प-पेपर की आपूर्ति के लिए निर्धारित समय को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि वादी को अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन में सुधार करने या आवश्यक स्टाम्प-पेपर की आपूर्ति करने के लिए, जैसा भी मामला हो, असाधारण प्रकृति के किसी भी कारण से रोका गया था और ऐसा समय आगे बढ़ाने से इनकार,वादी के लिए गंभीर अन्याय का कारण बनेगा।"

(7) आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के खंड (डी),के अवलोकन से पता चलता है जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा एकमात्र निर्भरता रखी गई थी, जब दावे में किए गए अभिकथनों किसी भी कानून द्वारा वर्जित किया गया प्रतीत होता है एक दावे को निचली अदालत द्वारा केवल तभी खारिज किया जा सकता है, ।इसलिए, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, निचली अदालत को केवल दावे में किए गए कथनों पर गौर करना होगा।दावे में किए गए कथनों को कुछ समय के लिए और आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के उद्देश्य के लिए सही माना जाना चाहिए। तथ्य के किसी भी विवादित

प्रश्न पर निचली अदालत द्वारा दावे को खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत तर्क नहीं दिया जा सकता है या उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(8) इसके अलावा, सी. पी. सी. की धारा 9, जो इसके तहत पुनः प्रस्तुत की गई है, यह निर्धारित करती है कि नागरिक अधिकारों से संबंधित प्रत्येक दावा, दीवानी न्यायालय के समक्ष तब तक दायर किया जा सकता है जब तक कि वह किसी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित न होः-

"धारा 9-अदालतें सभी दीवानी मुकदमों की सुनवाई तब तक करेंगी जब तक कि वे प्रतिबंधित न हों -न्यायालयों को (इसमें निहित प्रावधानों के अधीन) उन मुकदमों जिनमें उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है, को छोड़कर नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

स्पष्टीकरण I-एक मुकदमा जिसमें संपत्ति या पद के अधिकार का विरोध किया जाता है, वह एक नागरिक प्रकृति का मुकदमा है, इसके बावजूद कि ऐसा अधिकार पूरी तरह से धार्मिक संस्कारों या समारोहों के बारे में प्रश्नों के निर्णय पर निर्भर हो सकता है।स्पष्टीकरण II-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह मायने नहीं रखता कि स्पष्टीकरण-I में निर्दिष्ट कार्यालय से कोई शुल्क संलग्न है या नहीं या ऐसा कार्यालय किसी विशेष स्थान से संलग्न है या नहीं।"

(9) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सी. पी. सी. की धारा 9 की उपरोक्त भाषा यह स्पष्ट करती है कि किसी भी नागरिक अधिकार के उल्लंघन का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया कोई भी मुकदमा, किसी भी संपत्ति के अधिकार से बहुत कम, अनिवार्य रूप से बनाए रखने योग्य है।दीवानी मुकदमे की रखरखाव क्षमता का बहिष्करण केवल एक अपवाद है।उस अपवाद की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए, अन्यथा, किसी भी उदार व्याख्या से पीड़ित व्यक्ति को सुनने के अवसर से वंचित किया जा सकता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए बाध्य है।

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, किसी भी वैधानिक प्रावधान की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं हुए हैं, जो वर्तमान दावे को प्रतिबंधित करता है।हालाँकि, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलों से सहमत होने में असमर्थ है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भार्गवी कंस्ट्रक्शंस (ऊपर) में दिए गए निर्णय पर निर्धारित कानून की पूर्व स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है, जो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया जा रहा है, हालांकि, इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामला उस मामले में शामिल तथ्यों पर पूरी तरह से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि उस मामले में वादी ने कभी भी लोक अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया था।उनका एकमात्र दावा सबसे अच्छा था यह था कि उन्होंने मुकदमे के दायरे को नहीं समझा था

या उन्हें किसी गलत बयानी से गुमराह किया गया था।उस मामले में लोक अदालत के समक्ष पूर्ण अनुपस्थिति का अनुरोध भी नहीं किया गया था।इसलिए, उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति, जो निर्विवाद रूप से लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार था, को लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कोई शिकायत थी, तो वह उक्त निर्णय को चुनौती देने के लिए रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।उस मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित पक्ष को उपचार के बिना नहीं छोड़ा था, लेकिन चूंकि लोक अदालत का निर्णय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत अपील योग्य नहीं था, इसलिए पीड़ित व्यक्ति को रिट याचिका के उपचार का हकदार ठहराया गया था।हालाँकि, वर्तमान मामले में, दावे में वादी का सकारात्मक दावा और कथन यह है कि उन्हें कभी भी उन कार्यवाही में अदालत से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था जहां लोक अदालत ने उक्त पुरस्कार पारित किया था।उक्त अवार्ड वादी के प्रतिरूपण के माध्यम से की गई धोखाधड़ी पर आधारित था।उस स्थिति में, वादी को उक्त कार्यवाही में पक्षकार के रूप में भी नहीं लिया जा सकता है।अतः, वादी द्वारा दायर मुकदमे में कोई दोष नहीं पाया जा सका।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि धोखाधड़ी पर आधारित कोई भी आदेश, भले ही वह सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश हो; लेकिन धोखाधड़ी के माध्यम से, दीवानी न्यायालय के समक्ष बहुत अच्छी तरह से चुनौती दी जा सकती है।इस

तरह के मुकदमे को बनाए रखने योग्य बनाने का कानूनी सिद्धांत यह है कि ऐसे मुकदमे में चुनौती धोखाधड़ी को दी जाती है, न कि अदालत के आदेश को। कानून को धोखेबाज के पक्ष में खड़े होते हुए भी नहीं देखा जा सकता, उसकी रक्षा करना तो दूर की बात है। वर्तमान मामले में, जहां तक कथनों का संबंध है, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन के उद्देश्य के लिए, यह विवादित नहीं है कि वादी ने विशेष रूप से दावा किया है कि उसका प्रतिरूपण किया गया था। इसलिए, केवल इसी कारण से; उसका सूट पूरी तरह से रखरखाव योग्य है। इस संबंध में निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में कोई गलती नहीं पाई जा सकी।

(11) आगे कहा कि जहां तक याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए दूसरे बिंदु का संबंध है, इस न्यायालय को निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।यह भी एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि न्यायपालिका कानून और तथ्यों का एक मिश्रित सवाल है।किसी भी पहलू, जो कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है, को आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को बनाए रखने के लिए एक आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के उद्देश्य के लिए, दलीलों को सही माना जाना चाहिए और उसके बाद ही न्यायालय को यह आकलन करना होगा कि आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. में उल्लिखित आधारों में से कोई भी मौजूद है या नहीं।इसलिए,

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के इस तर्क को भी केवल अस्वीकार करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(12)आगे कहा कि इस न्यायालय ने प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में भी दम पाया कि, कम से कम, वादी संख्या 2 लोक अदालत के समक्ष या पहले के मुकदमे में कार्यवाही का पक्षकार नहीं था, जिसे केवल वादी संख्या 1 द्वारा दायर और वापस लिया गया था।चूँकि वादी सं. 2 भी वर्तमान मुकदमे में एक सह-वादी है, इसलिए वर्तमान दावा को आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था कि मुकदमा पुनर्निरीक्षण के कारण बनाए रखने योग्य नहीं था या वादी सं. 1 द्वारा पहले के मुकदमे को वापस लेने के कारण या रोक दिया गया था। दावे में किए गए अभिकथनों के अनुसार, पहले के मुकदमे को वापस लेने का कारण यह था कि प्रतिवादी द्वारा किए गए वादे के कारण कार्रवाई का कारण अस्तित्व में नहीं था, जो केवल वादी संख्या 1 का बेटा है। वर्तमान मुकदमा कार्रवाई के नए कारण पर दायर किया गया है।

(13) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, इसे खारिज कर दिया जाता है।हालाँकि, यहाँ

ऊपर दी गई किसी भी बात की सुनवाई के दौरान मामले के गुण- दोष, यदि कोई हो , पर कोई अभिव्यक्ति नहीं होगी।

त्रिभुवन दहिया

सुमन देवी ट्रांसलेटर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।